बुधवार
05 अगस्त 2026
● देहरादून
● वर्ष 34
● अंक 193
● पृष्ठ 8
● मूल्य ₹ 1.00

34 साल से देहरादून का विश्वास

दूनवैलीमेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94 email: doonvalley_news@yahoo.com Website: dunvalleymail.com डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

अवैध खनन के दौरान हुए हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत

❑उग्र भीड ने शव सडक पर रखकर किया प्रदर्शन

हमारे संवाददाता

देहरादून। राजधानी देहरादून में हो रहे अवैध खनन के चलते एक ट्रैक्टर चालक की मौत हो गयी। जिस पर गुस्साये परिजनों व स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही के साथ ही मुआवजा देने की मांग की।

मामला देहरादून के सेलाकुई थाना क्षेत्र के भाऊवाला का है, जहां अवैध खनन के दौरान हुए हादसे में एक ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग की।

जानकारी के अनुसार, बिहार के समस्तीपुर निवासी रूपन सिंह ट्रैक्टर-ट्रॉली चला रहे थे। इसी दौरान वन सुरक्षा दल ने उन्हें कथित रूप से अवैध खनन करते हुए देखा और उनका पीछा शुरू कर दिया। पीछा किए जाने के दौरान रूपन सिंह ट्रैक्टर-ट्रॉली के पहिए की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर फैलते ही मृतक के परिजन और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भाऊवाला पुल के पास एकत्र हो गए। उन्होंने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मृतक के आश्रितों को उचित आर्थिक सहायता व मुआवजा देने की मांग की। वहीं प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों को शांत कराने का प्रयास करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया।

सोशल मीडिया पर महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार

हमारे संवाददाता

बागेश्वर। सोशल मीडिया पर महिला के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से महिला की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहा था।

जानकारी के अनुसार बीती 30 जुलाई को पीड़िता द्वारा थाना कपकोट में तहरीर देकर बताया गया था कि एक व्यक्ति जिसका नाम जगदीश गोस्वामी है उसके द्वारा पीड़िता को बदनाम करने की नीयत से चरित्र पर लांछन लगाते हुए सोशल मीडिया साइड पर वीडियो अपलोड कर दिया गया है।

वहीं दो अगस्त को धर्मेन्द्र सिंह दानू पुत्र दिवान सिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया गया। जिसमें आरोप लगाया गया कि जगदीश गोस्वामी द्वारा

विधायक को बदनाम करने व उनकी छवि को धूमिल करने की नियत से सोशल मीडिया में गाली गलौच कर भ्रामक वीडियो प्रसारित किया गया है। पुलिस ने दोनो मामलों में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। मुकदमा दर्ज होने के उपरांत आरोपी लगातार फरार चल रहा था जिसके घर तथा सम्भावित स्थानो पर दबिश दी गयी घर पर न मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वांरट प्राप्त किये साथ ही आरोपी के निवास स्थान पर नियमानुसार मुनादी करायी गयी। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस टीम द्वारा उसके मोबाइल नम्बर की लोकेशन के आधार पर रानीखेत, रामनगर ,बिजनौर, हरिद्वार, सहारनपुर एव देहरादून इत्यादि क्षेत्रो में पीछा करते हुए आरोपी के सम्भावित ठहरने के स्थानो पर दबिश दी गयी । जिसके चलते पुलिस व एसओजी टीम द्वारा आरोपी को थाना बैजनाथ क्षेत्रान्तर्गत पिंगलौ बैण्ड कन्धार तिराहा यात्री विश्राम गृह के सामने से गिरफ्तार किया गया है। जिसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

दून वैली मेल

संपादकीय

चढ़ावा चोरी पर संसद में संग्राम

अयोध्या का राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है। करोड़ों लोगों की आस्था, वर्षों के संघर्ष और राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतीक है। इसलिए जब राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी या अनियमितता का मुद्दा संसद तक पहुँचता है, तो यह केवल विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का विषय नहीं रह जाता। यह देश की आस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रश्न बन जाता है। संसद में इस मुद्दे पर जिस तरह हंगामा हुआ, उसने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हम हर संवेदनशील विषय को राजनीतिक लाभ-हानि के तराजू पर तौलने लगे हैं? सत्ता पक्ष विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाता है, तो विपक्ष सरकार से जवाब मांगता है। लेकिन इस शोर-शराबे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल कहीं पीछे छूट जाता है सच्चाई क्या है? यदि चढ़ावे में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है, तो उसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। यदि आरोप निराधार हैं, तो तथ्यों के साथ उन्हें खारिज किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में न तो आरोपों को बिना जांच के सच मान लिया जाना चाहिए और न ही केवल राजनीतिक असुविधा के कारण सवाल पूछने वालों को खामोश करने की कोशिश होनी चाहिए।

राम मंदिर में देश-विदेश से श्रद्धालु करोड़ों रुपये, सोना-चांदी और अन्य मूल्यवान वस्तुएँ श्रद्धा के साथ अर्पित करते हैं। यह केवल धन नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास है। उस विश्वास की रक्षा करना मंदिर प्रशासन, संबंधित ट्रस्ट और सरकार सभी की साझा जिम्मेदारी है। इसलिए वित्तीय लेन-देन, दान और चढ़ावे के प्रबंधन में उच्च स्तर की पारदर्शिता अनिवार्य है। दूसरी ओर, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वह तथ्यात्मक आधार पर सवाल उठाए। यदि उसके पास दस्तावेज या ठोस प्रमाण हैं, तो उन्हें सार्वजनिक करे और निष्पक्ष जांच की मांग करे। लेकिन यदि केवल राजनीतिक माहौल बनाने के लिए आरोप लगाए जाते हैं, तो इससे लोकतांत्रिक विमर्श कमजोर होता है और जनता का भरोसा भी प्रभावित होता है। संसद बहस का मंच है, शोर का नहीं। यदि हर संवेदनशील मुद्दा केवल नारेबाजी में बदल जाएगा, तो समाधान कभी नहीं निकलेगा। जनता यह अपेक्षा करती है कि संसद में आरोपों का जवाब तथ्यों से दिया जाए, न कि केवल राजनीतिक नारों से। यह मामला केवल राम मंदिर का नहीं है। देश के सभी बड़े धार्मिक संस्थानों चाहे वे मंदिर हों, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में प्राप्त दान और चढ़ावे के प्रबंधन में पारदर्शिता और नियमित लेखा-परीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। आस्था जितनी बड़ी होती है, जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए।

राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। इसलिए उससे जुड़ा कोई भी आरोप अत्यंत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों को इस विषय पर संयम और जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। सरकार और संबंधित संस्थाओं को यदि कोई संदेह पैदा हुआ है, तो उसे दूर करने के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ तथ्यों को सामने रखना चाहिए। वहीं विपक्ष को भी तथ्य और प्रमाण के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए। आस्था का सम्मान तभी सुरक्षित रहेगा, जब उसके साथ जुड़ी हर व्यवस्था भी पारदर्शी और जवाबदेह होगी। संसद का दायित्व है कि वह इस विश्वास को मजबूत करे, न कि उसे राजनीतिक टकराव का माध्यम बनाए।

अतिक्रमण हटाओ अभियान की सराहना की, दिए सुझाव!

संवाददाता

देहरादून। नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान की सराहना करते हुए संयुक्त नागरिक संगठन के समन्वयक नरेश चंद्र कुलाश्री ने नगर आयुक्त को लिखे पत्र में अभियान को पूरा करने हेतु दिए सुझाव।

पत्र में बताया गया है की नगर के मुख्यमार्गों, पलटन बाजार एवं आवासीय क्षेत्रों की सड़कों, फुटपाथों, नालियों एवं फ्लाई ओवर के नीचे एवं आसपास के सार्वजनिक स्थलों में व्यावसायिक उपयोग हेतु अतिक्रमण के कारण सड़कों में यातायात जाम, दुर्घटना घटित होने के खतरे, आम जनता को वाहनों एवं पैदल चलने वाले राहगीरों को आवागमन में परेशानी, नालियों की गन्दगी एवं बारिश के पानी की निकासी अवरुद्ध होने से सड़कों में कीचड़ एवं जलभराव आदि की स्थिति में आम नागरिकों को एक जगह से दूसरी जगह आने-जाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण आजकल यह समस्या ज्यादा गम्भीर हो गई है। विगत में इन परिस्थितियों के कारण अनेक स्थानों में दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं।पत्र में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हालिया 3 अगस्त तथा 19 जून को दिए गए फैसलो को संदर्भित करते हुए सड़कों एवं फुटपाथों पर आम जनता का मौलिक अधिकार बताते हुए इस अधिकार को क्रियान्वित कराने की भी मांग की गई है।संगठन समन्वयक कुलाश्री ने आशा व्यक्त की है की अभियान में अतिक्रमण को स्थाई रूप से हटाकर दून वासियों की दिक्कतों का हमेशा के लिए समाधान हो सकेगा।

'बंद कमरे' और पहाड़ के 'खाली गाँव'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। दिल्ली में बैठक और कमरों के बंद दरवाजे। बाहर कैमरे खड़े हैं। अंदर नेता बैठे हैं। एजेंडा लिखा होगा संगठन, चुनाव, रणनीति, बूथ, विस्तार, 2027। लेकिन उत्तराखंड का आम आदमी शायद यह पूछना चाहता है क्या इन बैठकों में उसकी भी कोई सीट होती है? दिल्ली में उत्तराखंड भाजपा की बैठक सिर्फ एक संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं है। यह उस चुनावी तैयारी का हिस्सा है, जिसकी आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन राजनीति में चुनाव कभी दूर नहीं होते। चुनाव खत्म होते ही अगला चुनाव शुरू हो जाता है। बैठक में निश्चित रूप से समीक्षा होगी। किस जिले में संगठन मजबूत है, कहाँ कमजोर है। किस विधायक के खिलाफ नाराजगी है, कहाँ सरकार की योजनाएँ असर कर रही हैं, किस मुद्दे को आगे रखना है और किस मुद्दे को पीछे छोड़ देना है। लेकिन क्या कोई यह भी पूछेगा कि उत्तराखंड से लगातार हो रहे पलायन का क्या हुआ?क्या बैठक में यह चर्चा होगी कि जिन गाँवों में बूथ तो हैं, लेकिन मतदाता नहीं बचे, वहाँ लोकतंत्र किसके भरोसे खड़ा है?

यह वही उत्तराखंड है जहाँ चुनाव के समय हर सड़क विकास का प्रतीक बन जाती है और बरसात आते ही वही सड़क गड्ढों की पहचान बन जाती है, जहाँ हर साल रोजगार के वादे होते हैं और हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी नई चिंताओं के साथ तैयारी करते हैं। दिल्ली की बैठकों में आंकड़े रखे जाते हैं। कितने सदस्य बने, कितने बूथ जीते, कितनी योजनाएँ शुरू हुईं। लेकिन जनता के पास भी अपने आंकड़े हैं कितने युवा नौकरी की तलाश में राज्य छोड़ गए, कितने स्कूल बंद हुए, कितने गाँव खाली हुए और कितने अस्पताल

◆उत्तराखंड भाजपा की दिल्ली में होने वाली बैठक पर सवाल
◆दिल्ली में खिंचे कैमरे और बंद दरवाजों में 2027 की बिसात
◆समीक्षा बूथों की होगी या पलायन से खाली होते पहाड़ों की
◆भाजपा के माइक्रो-मैनेजमेंट के आगे पस्त पहाड़ के जनमुद्दे
◆रणनीति की मेज पर चुनाव और जनता की मेज पर सवाल

डाक्टरों का इंतजार करते रहे। भाजपा के लिए यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड में लगातार सत्ता में रहने के बाद एंटी-इन्कम्बेंसी एक स्वाभाविक चुनौती बनती है। पार्टी चाहेगी कि संगठन सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाए और असंतोष को कम करे। दूसरी तरफ विपक्ष भी इन्हीं बैठकों पर नजर रखे हुए है। कांग्रेस यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि भाजपा चुनावी गणित में व्यस्त है, जबकि जनता महँगाई, बेरोज़गारी और स्थानीय समस्याओं से जूझ रही है। लेकिन लोकतंत्र में सवाल केवल विपक्ष से नहीं, सत्ता से ज्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि निर्णय लेने की शक्ति सत्ता के पास होती है।

दिल्ली की बैठक में यदि केवल चुनाव जीतने की रणनीति बनेगी, तो वह राजनीतिक बैठक होगी। लेकिन यदि वहाँ यह भी तय होगा कि पहाड़ के खाली होते गाँव कैसे बसेंगे, युवाओं को स्थानीय रोजगार कैसे मिलेगा, पर्यटन का लाभ गाँव तक कैसे पहुँचेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ कैसे मजबूत होंगी तब वह केवल राजनीतिक बैठक नहीं, उत्तराखंड के भविष्य की बैठक होगी। उत्तराखंड की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में चेहरों से ज्यादा संगठन पर जोर दिया गया है। नेतृत्व परिवर्तन भी हुए, रणनीतियाँ भी बदलीं, लेकिन जनता का मूल्यांकन अंततः रोजमर्रा के जीवन से होता है। चुनावी नारे कुछ दिन चलते हैं, बिजली-पानी, सड़क, अस्पताल और रोजगार हर दिन चलते हैं। दिल्ली की यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह संकेत मिलेगा कि भाजपा 2027 के चुनाव में किस नैरेटिव के साथ उतरना चाहती है। क्या चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित होगा या स्थानीय सवालों को अधिक महत्व मिलेगा? क्या संगठन में बदलाव होंगे? क्या कुछ नेताओं की जिम्मेदारियाँ बदलेंगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीनों में स्पष्ट होंगे।

राजनीतिक दलों की बैठकें लोकतंत्र का हिस्सा हैं। रणनीति बनाना उनका अधिकार है। लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा बैठक खत्म होने के बाद शुरू होती है। जब नेता दिल्ली से लौटेंगे, तब जनता

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

'ग्राउंड वर्सेज लीगल फाइट'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की उलटी गिनती अभी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी तैयारी तेज कर दी है। भाजपा बूथ मजबूत करने में लगी है, तो कांग्रेस अब एसआईआर को लेकर कानूनी मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही है। खबर है कि कांग्रेस ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए वकीलों की एक टीम तैयार की है। पहली नजर में यह केवल संगठनात्मक तैयारी लग सकती है। लेकिन इसके पीछे लोकतंत्र का एक बड़ा सवाल छिपा है क्या चुनाव अब केवल जनता के बीच लड़े जाएंगे, या अदालतों और निर्वाचन आयोग के दफ्तरों में भी?

मतदाता सूची किसी भी चुनाव की रीढ़ होती है। अगर सूची पर विवाद खड़ा हो जाए, तो चुनाव परिणाम आने से पहले ही अविश्वास का माहौल बन सकता है। कांग्रेस का कहना है कि वह यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई पात्र मतदाता सूची से बाहर न हो और किसी प्रकार की अनियमितता न होने पाए। इसलिए उसने कानूनी विशेषज्ञों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। भाजपा का पक्ष अलग होगा। वह कहेगी कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और उसकी प्रक्रिया पर बेवजह संदेह पैदा करना उचित नहीं। सत्ता पक्ष यह भी तर्क दे सकता है कि यदि किसी को आपत्ति है तो उसके लिए आयोग ने कानूनी प्रक्रिया पहले से तय कर रखी है। लेकिन राजनीति में सवाल वहीं खत्म नहीं होते जहाँ बयान खत्म होते हैं।

उत्तराखंड का चुनाव हमेशा पहाड़ और मैदान, पलायन और रोजगार, सड़क और स्वास्थ्य, सैनिक और किसान जैसे मुद्दों के बीच लड़ा जाता रहा है। इस बार यदि मतदाता सूची भी बड़ा मुद्दा बनती है, तो चुनाव का स्वरूप बदल सकता है। कांग्रेस की रणनीति यह संकेत देती है कि वह चुनाव के दिन से पहले ही चुनावी प्रक्रिया पर पूरी निगरानी रखना चाहती है। हर

❑कांग्रेस कानूनी तैयारी में और भाजपा बूथों पर किलेबंदी में व्यस्त
❑कांग्रेस पार्टी की नजर बैलट से पहले वोटर लिस्ट के कागजात पर
❑वकीलों की फौज तैयार, चुनावी जंग अब अदालत व आयोग तक

विधानसभा क्षेत्र में यदि कानूनी टीम सक्रिय रहती है, तो बूथ स्तर पर उठने वाले विवादों को तुरंत आयोग के सामने रखा जा सकेगा। यह एक राजनीतिक रणनीति भी है और एहतियाती कदम भी। लेकिन एक सवाल कांग्रेस से भी पूछा जाना चाहिए। यदि मतदाता सूची इतनी महत्वपूर्ण है, तो क्या पार्टी ने पिछले वर्षों में भी बूथ स्तर पर उतनी ही गंभीरता से काम किया? क्या केवल चुनाव नजदीक आने पर कानूनी तैयारी पर्याप्त होगी, या जनता के बीच संगठन की मजबूती भी उतनी ही जरूरी है?

दूसरी ओर, भाजपा के लिए भी यह समय आत्मविश्वास के साथ-साथ पारदर्शिता दिखाने का है। यदि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष है, तो हर आपत्ति का जवाब तथ्यों और नियमों के आधार पर दिया जाना चाहिए। लोकतंत्र में विश्वास केवल जीत से नहीं, बल्कि प्रक्रिया की निष्पक्षता से बनता है। दरअसल, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मतदाता है। और मतदाता की सबसे बड़ी पहचान उसका नाम मतदाता सूची में होना है। यदि कोई पात्र नागरिक सूची से बाहर रह जाए, तो उसका मतदान का अधिकार प्रभावित होता है। इसलिए मतदाता सूची का शुद्ध और अद्यतन होना किसी एक दल का नहीं, पूरे लोकतंत्र का विषय है।

2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी रणनीति तय करनी शुरू कर दी है। भाजपा संगठन और सरकार के कामकाज के सहारे चुनावी मैदान तैयार कर रही है। कांग्रेस चुनावी प्रक्रिया पर निगरानी और कानूनी तैयारी के जरिए अपनी सक्रियता दिखा रही है। आने वाले महीनों में यह मुकाबला केवल रैलियों और सभाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दस्तावेज़ों, नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं तक भी पहुंचेगा। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, लेकिन यह उत्सव तभी सार्थक है जब हर पात्र मतदाता बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का उपयोग कर सके।

यदि कांग्रेस की कानूनी टीम चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में योगदान देती है, तो यह लोकतंत्र के लिए सकारात्मक कदम हो सकता है और यदि यह केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का माध्यम बनती है, तो जनता इसे भी चुनावी रणनीति का हिस्सा मानेगी। आखिरकार, चुनाव केवल वोटों से नहीं जीते जाते विश्वास से भी जीते जाते हैं और विश्वास की शुरुआत मतदाता सूची से होती है।

पंचायतों की समस्याओं के समाधान को लेकर प्रधान संगठन मुखर, सौंपा ज्ञापन

अल्मोड़ा(आरएनएस)। ग्राम प्रधानों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर ग्राम प्रधान संगठन हवालबाग ने मुख्य विकास अधिकारी के नाम सहायक खंड विकास अधिकारी हवालबाग के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। इससे पहले विकासखंड कार्यालय में आयोजित बैठक में ग्राम प्रधानों ने पंचायतों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर उनके शीघ्र समाधान की मांग उठाई।

ज्ञापन में कहा गया कि ग्राम पंचायतों का गठन हुए लगभग एक वर्ष बीत जाने के बावजूद अधिकांश ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के प्रस्ताव अभी तक ऑनलाइन अपलोड नहीं हो पाए हैं, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रधानों ने जीपीडीपी प्रस्तावों को शीघ्र ऑनलाइन अपलोड कराने और तकनीकी समस्याओं के समाधान की मांग की। प्रधानों ने वीबीजी-रामजी योजना में श्रमिकों की उपस्थिति सहित अन्य प्रक्रियाओं में ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन व्यवस्था लागू करने तथा पर्वतीय क्षेत्रों की परिस्थितियों के अनुरूप योजना के प्रावधानों में संशोधन की मांग की। साथ ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में अन्य विभागों द्वारा कराए जाने वाले विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायत की अनुमति और कार्य पूर्ण होने पर एनओसी अनिवार्य किए जाने की मांग भी उठाई। ज्ञापन में श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 300 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये करने, निर्माण सामग्री का भुगतान 15 दिनों के भीतर करने, वीबीजी-रामजी योजना में सुरक्षा दीवारों को शामिल करने, ग्राम पंचायतों को आवश्यक कार्य उपकरण उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक कार्य के एस्टीमेट में वर्कमेट का प्रावधान लागू करने की मांग की गई। इसके अलावा ग्राम प्रधान का मानदेय 15 हजार रुपये और उपप्रधान का मानदेय 5 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग भी की गई।

प्रधान संगठन का कहना था कि ग्राम प्रधान गांव के विकास की धुरी होने के साथ ही चौबीसों घंटे ग्रामीणों की सेवा में जुटा रहता है, इसलिए उसे उसके दायित्वों के अनुरूप सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रधान संगठन अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नयाल, महामंत्री विनोद जोशी, उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह मेहरा, नवीन भट्ट, पूरन सिंह, कमल भाकुनी, मनोहर सिंह, वीरेंद्र सिंह, नंदन सिंह, प्रकाश आर्या, ललिता देवी, हरीश आर्या, भावना देवी, ममता पांडे, सोनिया देवी, रमेश भोज सहित बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान एवं उपप्रधान मौजूद रहे।

एसआईआर नोटिस जारी होने के विरोध में बंगाली समाज का प्रदर्शन

रुद्रपुर(आरएनएस)। बंगाली कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप अधिकारी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में धरना-प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए मतदाता सूची में संशोधन के लिए एक माह का अतिरिक्त समय देने और प्रत्येक बूथ पर बीएलओ के साथ सक्षम अधिकारी की तैनाती की मांग की। इस संबंध में एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन में कहा गया कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची के आधार पर जिन लोगों ने पहले ही अपने नाम का संशोधन करा लिया था और बीएलओ को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा दिए थे, उन्हें भी नोटिस जारी किए गए हैं। ऊधमसिंह नगर के दिनेशपुर, शक्तिफार्म, खटीमा, झनकैया, सितारगंज, रुद्रपुर, ट्रांजिट कैंप, रवींद्रनगर, संजय नगर, आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी, जगतपुरा और मुखर्जी नगर क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मतदाताओं को नोटिस मिले हैं। कई स्थानों पर करीब एक हजार मतदाताओं में से लगभग 700 को नोटिस जारी होने का दावा किया गया। समिति ने कहा कि छह और नौ अगस्त तक की समय सीमा निर्धारित है, जबकि कई जरूरी प्रमाणपत्र बनवाने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। ऐसे में संशोधन के लिए कम से कम एक माह का अतिरिक्त समय दिया जाए। साथ ही प्रत्येक बूथ पर बीएलओ के साथ सक्षम अधिकारी की तैनाती कर मौके पर ही आपत्तियों और दस्तावेजों का निस्तारण कराया जाए।

समिति ने चेतावनी दी कि समय पर संशोधन का अवसर नहीं मिलने से मतदाता सूची से नाम कटने पर बंगाली समाज के हजारों मतदाताओं को नुकसान हो सकता है। धरना-प्रदर्शन में पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर गांगुली, परिमल राय, पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन, ममता हालदार, नगर अध्यक्ष अर्जुन विश्वास, नारायण महाजन, पंकज दास गुप्ता, त्रिनाथ विश्वास, नारायण हालदार, किशोर हालदार, सुभाष व्यापारी, समीर राय, तपन कुमार घरानी, उमाशंकर मंडल, मनोरंजन साना, गोपाल विश्वास, बाबू ढाली, जगदीश दास, जय तरफदार, शैलेंद्र तरफदार, परितोष मंडल समेत बड़ी संख्या में समिति पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *सांध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

–प्रबंधक विज्ञापन

पहाड़ की संस्कृति पर 'डिजिटल' प्रहार

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड की पहचान केवल हिमालय की बर्फीली चोटियों, देवस्थलों और प्राकृतिक सौंदर्य से नहीं है। इस प्रदेश की असली ताकत उसकी लोक संस्कृति, लोकगीतों और पारंपरिक लोककलाओं में बसती है। इन्हीं अमूल्य धरोहरों में एक है झुमेलो एक ऐसा लोकनृत्य जो केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि पहाड़ के सामाजिक जीवन, सामूहिकता और सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। आज जब आधुनिकता और डिजिटल संस्कृति गांवों तक पहुंच चुकी है, तब झुमेलो जैसी लोककलाएं अपने अस्तित्व की चुनौती से जूझ रही हैं। सवाल यह है कि क्या आने वाली पीढ़ियां केवल मोबाइल स्क्रीन पर रील्स देखेंगी, या फिर ढोल-दमाऊ की थाप पर झूमते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी जुड़ेंगी?

झुमेलो उत्तराखंड, विशेष रूप से गढ़वाल क्षेत्र का लोकप्रिय पारंपरिक लोकनृत्य और लोकगायन है। इसका नाम ही झूमने से निकला माना जाता है। इसमें महिलाएं और पुरुष समूह बनाकर गोलाकार या अर्धवृत्त में खड़े होकर तालबद्ध कदमों और मधुर गीतों के साथ नृत्य करते हैं। इस नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सहजता है। इसमें मंच, चमकदार रोशनी या आधुनिक साज-सज्जा की जरूरत नहीं होती। गांव का चौक, खेत की मेड़, मंदिर का आंगन या किसी मेले का खुला मैदान ही इसका सबसे बड़ा मंच बन जाता है। झुमेलो की आत्मा उसके लोकवाद्य हैं। ढोल, दमाऊ, रणसिंघा, हुड़का और बांसुरी की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण को जीवंत बना देती है। जैसे ही ढोल की पहली थाप पड़ती है, लोग स्वत: ही नृत्य की लय में बंध जाते हैं।

झुमेलो के गीतों में प्रेम, प्रकृति, ऋतु परिवर्तन, देवी-देवताओं की महिमा, खेती-बाड़ी, सामाजिक रिश्ते और पहाड़ के संघर्ष की झलक मिलती है। यह केवल संगीत नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही लोक स्मृतियों का मौखिक इतिहास भी है। पहाड़ का जीवन हमेशा सामूहिक रहा है। खेती हो, शादी-ब्याह हो, मेले-त्योहार हों या किसी देवता का उत्सव हर अवसर पर पूरा गांव एक परिवार की तरह शामिल होता है। झुमेलो इसी सामूहिक जीवन का सांस्कृतिक विस्तार है। यह नृत्य किसी एक कलाकार का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि पूरे समाज की सहभागिता का प्रतीक होता है। यहां दर्शक और कलाकार के बीच कोई दीवार नहीं होती। हर व्यक्ति इस उत्सव का हिस्सा बन जाता है।

झुमेलो केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है। इसके गीतों में सामाजिक संदेश भी छिपे होते हैं। कहीं बेटी के सम्मान की बात होती है, कहीं प्रकृति संरक्षण का संदेश, तो कहीं मेहनत और ईमानदारी का महत्व। पहाड़ की लोककलाएं हमेशा समाज को जोड़ने का माध्यम रही हैं। उन्होंने बिना किसी औपचारिक शिक्षा के लोगों को संस्कृति, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ाया।

समय के साथ गांवों से पलायन बढ़ा। रोजगार और शिक्षा के लिए युवा शहरों की ओर चले गए। गांव खाली होने लगे और उनके साथ लोककलाओं की जीवंत परंपरा भी कमजोर पड़ने लगी। आज कई गांव ऐसे हैं जहां पहले हर त्योहार पर झुमेलो की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन अब वहां सन्नाटा पसरा रहता है। विवाह समारोहों में लोकवाद्यों की जगह डीजे ने ले ली है। पारंपरिक गीतों की जगह फिल्मी संगीत बजने लगा है। यह बदलाव केवल मनोरंजन का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत के क्षरण का संकेत भी है। सकारात्मक बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड के कई युवा कलाकार, सांस्कृतिक संस्थाएं और सोशल मीडिया मंच झुमेलो सहित अन्य लोककलाओं को नई पहचान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं।

◆अस्तित्व के संकट से जूझती देवभूमि की सांस्कृतिक धरोहर झुमेलो
◆पहाड़ में दुख-सुख व सांस्कृतिक चेतना का था कभी जीवंत माध्यम
◆मोबाइल रील्स व आधुनिकता के बीच गुम हो रही हैं लोक परंपराएं
◆सिर्फ एक नृत्य नहीं पहाड़ की सामूहिक आत्मा का उत्सव था झुमेलो

यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोकगीतों और पारंपरिक नृत्यों के वीडियो लाखों लोग देख रहे हैं। विद्यालयों, महाविद्यालयों और सांस्कृतिक महोत्सवों में भी झुमेलो को मंच मिल रहा है। यदि इस प्रयास को सरकारी संरक्षण और समाज का सहयोग मिले, तो यह परंपरा नई पीढ़ी के बीच और मजबूत हो सकती है। उत्तराखंड में धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन के साथ-साथ सांस्कृतिक पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। यदि स्थानीय मेलों, होम-स्टे, पर्यटन उत्सवों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में झुमेलो को नियमित स्थान मिले, तो यह न केवल संस्कृति को जीवित रखेगा बल्कि स्थानीय कलाकारों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। लोककला केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि भविष्य की आर्थिक ताकत भी बन सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि झुमेलो जैसी लोककलाओं को बचाने के लिए केवल सरकारी योजनाएं पर्याप्त नहीं होंगी। परिवार, विद्यालय, ग्राम सभाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं और स्थानीय समुदाय सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। स्कूलों में लोकनृत्य और लोकसंगीत को सह-पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। ग्राम स्तर पर सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन हो। वरिष्ठ लोक कलाकारों का सम्मान और उनके अनुभव का दस्तावेजीकरण किया जाए। डिजिटल माध्यमों पर लोककला का संग्रह और प्रचार-प्रसार बढ़ाया जाए। युवा कलाकारों को आर्थिक और संस्थागत सहयोग दिया जाए। झुमेलो केवल एक लोकनृत्य नहीं, बल्कि उत्तराखंड की आत्मा की धड़कन है। यह उस समाज की कहानी कहता है जिसने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी गीत, संगीत और सामूहिकता को कभी नहीं छोड़ा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि विकास की दौड़ में हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों को न भूलें। क्योंकि जिस समाज की लोककलाएं जीवित रहती हैं, उसकी पहचान भी जीवित रहती है। ढोल-दमाऊ की हर थाप और झुमेलो का हर कदम हमें यही याद दिलाता है कि आधुनिकता का स्वागत करें, लेकिन अपनी संस्कृति की कीमत पर नहीं। यही उत्तराखंड की असली पहचान है, और यही उसकी सबसे बड़ी विरासत।

बिजली बिलों की गड़बड़ी पर डीएम ने लगाई फटकार

बागेश्वर(आरएनएस)। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता दरबार में सड़क, आधारभूत ढांचा, बिजली, पेयजल, आपदा समेत विभिन्न विभागों से जुड़ी 26 शिकायतें दर्ज हुईं। अधिकांश मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस दौरान बिजली बिलों में मिल रही विसंगतियों पर जिलाधिकारी अपूर्वा पांडे ने नाराजगी जताते हुए ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता को कड़ी फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने एक माह के भीतर सभी बिजली बिलों की जांच कर त्रुटियों को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी उपभोक्ता से अनावश्यक या अतिरिक्त भुगतान नहीं कराया जाए। तय समय सीमा के बाद भी लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल और जनसुनवाई के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों का गंभीरता से समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रत्येक आयोजित होने वाली जनसुनवाई में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने और आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ प्रभावी समाधान करने को कहा। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब करते हुए सीएम हेल्पलाइन पर शत-प्रतिशत कॉलिंग सुनिश्चित करने और शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी एन.एस. नबियाल, मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

पुराने स्टाइल में बालों को कर्ल करने के लिए इस्तेमाल करें रोलर, जानें आसान तरीका

बालों को कर्ल करने के लिए कई तरीके हैं, जिनमें से एक है रोलर का इस्तेमाल करना। यह तरीका न केवल आसान है, बल्कि इसके जरिए आप अपने बालों को एक अलग और आकर्षक लुक दे सकती हैं। रोलर का इस्तेमाल करके आप बिना हीटिंग उपकरणों के अपने बालों को कर्ल कर सकती हैं। इस लेख में हम आपको रोलर का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कुछ टिप्स देंगे, जिससे बाल पुराने समय की तरह कर्ल हो जाएंगे।

बालों को तैयार करें : रोलर का इस्तेमाल करने से पहले अपने बालों को अच्छी तरह से धो लें। इसके लिए एक हल्के शैंपू और कंडीशनर का उपयोग करें। इसके बाद बालों को तौलिये से हल्का-सा सुखा लें, ताकि उनमें नमी बनी रहे, लेकिन वे गीले न हों। इससे रोलर आसानी से बालों में सेट हो सकेंगे और कर्ल लंबे समय तक टिके रहेंगे। इसके अलावा बालों में कुछ हल्का स्टाइलिंग उत्पाद लगाएं, ताकि कर्ल अच्छे से सेट हो सकें।

सही आकार और प्रकार चुनें : रोलर कई आकार और प्रकार में आते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने बालों की लंबाई और मोटाई के अनुसार सही रोलर चुनें। छोटे रोलर छोटे कर्ल बनाने के लिए अच्छे होते हैं, जबकि बड़े रोलर लंबे और बड़े कर्ल के लिए बेहतर होते हैं। इसके अलावा आप अलग-अलग प्रकार के रोलर, जैसे कि वेल्क्रो रोलर, सॉफ्ट रोलर और प्लास्टिक रोलर भी आजमा सकती हैं। यह आपके बालों की जरूरत और स्टाइल पर निर्भर करता है।

बालों को हिस्सों में बांटे : रोलर लगाने से पहले अपने बालों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें। इससे यह आसान हो जाएगा कि आप हर हिस्से पर ध्यान दे सकें और सभी बालों को समान रूप से सेट कर सकें। इसके लिए पहले बालों को बीच से अलग करके 2 हिस्सों में बांट लें, फिर हर हिस्से को छोटे-छोटे सेक्शन में बांटकर रोलर लगाएं। इससे आपके कर्ल पूरे दिन टिके रहेंगे और आपके बालों को एक खूबसूरत लुक देंगे।

रोलर को सही तरीके से लगाएं : अब बारी आती है रोलर लगाने की। सबसे पहले एक हिस्से को लें और उसे रोलर पर लपेटें, फिर उसे जड़ों तक पहुंचाएं। इसके बाद रोलर को हल्का-सा दबाकर पिन या क्लिप से अच्छी तरह से बांधें, ताकि वह जगह पर टिका रहे। इसी तरह सभी हिस्सों पर रोलर लगाएं। अगर आप चाहें तो रोलर को रातभर लगा रहने दें और सुबह उठकर उन्हें हटा दें। इससे आपके बालों को एक खूबसूरत लुक मिलेगा।

सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल करें : रोलर हटाने के बाद अपने नए कर्ल पर सेटिंग स्प्रे लगाएं, ताकि वे लंबे समय तक टिके रहें। सेटिंग स्प्रे बालों को स्थिरता देता है और उन्हें उलझने से बचाता है। इसके अलावा सेटिंग स्प्रे आपके कर्ल को पूरे दिन प्राकृतिक जैसा बनाए रखता है। अगर आप चाहें तो हल्का-सा तेल भी लगा सकते हैं, ताकि आपके कर्ल चमकदार दिखें और मुलायम महसूस हों। इससे आपके बालों को एक बेहतरीन लुक मिलेगा।

आंखों की थकान का कारण बन सकती है ज्यादा स्क्रीन टाइम, जानिए इसके लक्षण

आज के समय में स्क्रीन टाइम का बढ़ता उपयोग आंखों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। चाहे वह कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन हो या टीवी, अधिक समय तक स्क्रीन के सामने बैठने से आंखों की थकान हो सकती है। यह लेख आपको कुछ शुरुआती लक्षणों के बारे में बताएगा, जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी आंखें थकी हुई हैं और आपको किन सावधानियों का पालन करना चाहिए।

आंखों की जलन और खुजली होना : अगर आपको स्क्रीन देखते समय आंखों में जलन या खुजली महसूस हो तो इसे नजरअंदाज न करें। यह लक्षण बताता है कि आपकी आंखें अधिक समय तक स्क्रीन के सामने रहने के कारण थकी हुई हैं। इस स्थिति में तुरंत आंखों को आराम दें और उन्हें ठंडे पानी से धोएं या आंखों की बूंदों का उपयोग करें। इससे आपकी आंखों को राहत मिलेगी और वे थोड़ी देर के लिए आराम कर सकेंगी, जिससे आपकी आंखों की थकान कम होगी।

सिरदर्द होना : अगर आपको स्क्रीन देखते समय सिरदर्द होता है तो यह भी एक सामान्य समस्या है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह लक्षण बताता है कि आपकी आंखें और सिर एक-दूसरे पर ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, जिससे दर्द होता है। इस स्थिति में आंखों को आराम देना जरूरी है। थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से दूर रहें और आंखों को बंद करके कुछ मिनट आराम करें। इससे सिरदर्द कम होगा और आप बेहतर महसूस करेंगे।

आंखों का धुंधला दिखना : अगर आपको स्क्रीन देखते समय चीजें धुंधली दिखती हैं तो यह भी आंखों की थकान का संकेत हो सकता है। यह लक्षण बताता है कि आपकी आंखें स्क्रीन की रोशनी के कारण ज्यादा संवेदनशील हो गई हैं। इस स्थिति में आंखों को आराम देना जरूरी है। थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से दूर रहें और आंखों को बंद करके कुछ मिनट आराम करें।

लगातार झपकना : अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी आंखें बार-बार झपक रही हैं तो यह भी एक सामान्य संकेत हो सकता है। यह लक्षण बताता है कि आपकी आंखें स्क्रीन की रोशनी के कारण थकी हुई हैं। इस स्थिति में आंखों को आराम देना जरूरी है। थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से दूर रहें और आंखों को बंद करके कुछ मिनट आराम करें। इससे आपकी आंखों को राहत मिलेगी और वे थोड़ी देर के लिए आराम कर सकेंगी।

गर्मियों में ये प्राकृतिक चीजें कर सकती हैं सनस्क्रीन का काम

किसी के स्किन केयर किट में सबसे आवश्यक उत्पादों में से एक सनस्क्रीन है। यह त्वचा को सूरज की हानिकारक यूवी किरणों से बचाता है, जो सनबर्न, झुर्रियों और महीन रेखाओं का कारण बनती हैं। वैसे तो बाजार में कई सनस्क्रीन उपलब्ध हैं, लेकिन वह रसायनों से भरे हुए होते हैं। इस कारण आपको प्राकृतिक और घरेलू उपचारों का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए आज हम आपको सनस्क्रीन के रूप में बेहतरीन काम करने वाले 5 प्राकृतिक तत्व बताते हैं।

नारियल का तेल

यदि आप एक प्राकृतिक सनस्क्रीन की तलाश कर रहे हैं, जो आसानी से उपलब्ध हो तो नारियल का तेल सबसे अच्छा विकल्प है। यह हाइड्रेटिंग तेल सूरज की हानिकारक किरणों को 20 प्रतिशत तक रोक सकता है और त्वचा की रक्षा कर सकता है। यह स्ट्रेच मार्क्स से भी छुटकारा दिला सकता है अगर आप लंबे समय तक धूप में रहते हैं तो बेझिझक यह तेल लगा सकते हैं। यह आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज करने में भी मददगार है।

तिल का तेल

प्राकृतिक सनस्क्रीन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए तिल का तेल एक अच्छा विकल्प है। यह सूरज की हानिकारक यूवी किरणों को लगभग 30 प्रतिशत तक रोक सकता है। इससे आपकी त्वचा सनबर्न और महीन रेखाओं से बची रहेगी। एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर यह तेल झुर्रियों, रंगत और त्वचा की अन्य समस्याओं को कम करने के साथ सेहत के लिए भी लाभदायक है। इसमें मौजूद विटामिन- इ त्वचा को पर्यावरण प्रदूषण और विषाक्त पदार्थों से भी बचाता है।

शिया बटर

यदि आप बहुत कम समय के लिए बाहर जा रहे हैं तो शिया बटर का इस्तेमाल आराम से किया जा सकता है। इसका कारण है कि इसमें केवल 3 से 4 का अनुमानित एसपीएफ़ होता है। विटामिन- ए और इ से भरपूर शिया बटर संवेदनशील त्वचा के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट त्वचा को फ्री रैडिकल डैमेज से बचाते हैं, जिससे सूरज की क्षति से होने वाली जलन से राहत मिलती है।

एलोवेरा

एलोवेरा एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। यह त्वचा पर लालिमा, सनबर्न और सूजन को रोकने में अत्यधिक प्रभावी है। यह सूरज की यूवी किरणों के लगभग 20 प्रतिशत तक रोक सकता है। इसके साथ ही यह त्वचा को पोषण देकर और संक्रमण को कम करके त्वचा की बनावट में सुधार करता है। अगर आप सनबर्न की समस्या से परेशान हैं तो आप इससे राहत पाने के लिए कुछ ताजा एलोवेरा जेल लगा सकते हैं।

ग्रीन टी

ग्रीन टी पॉलीफेनोल एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। यह प्राकृतिक सन-ब्लॉकिंग एजेंट के रूप में कार्य करके त्वचा को सूरज की क्षति से बचाती है। इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण त्वचा की लालिमा, सूजन और जलन को कम करने में मदद करते हैं। लाभ के लिए ग्रीन टी को पानी के साथ उबालें, फिर इसे रातभर के लिए छोड़ दें। सुबह इस मिश्रण को छानकर इसके पानी को स्प्रे बोतल में डालें और बाहर निकलने से पहले इसे त्वचा पर स्प्रे करें।

शब्द सामर्थ्य -011

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. राजद प्रमुख 6. रखवाला, रक्षा करने वाला 7. दयालु, रहम करने वाला (उ.) 10. युग्म, जोड़ा, एक राशि, एक फिल्म अभिनेता 13. कैदखाना, जेल, हिरासत 15. जानकी, जनकनंदनी 17. व्यर्थ की बात, बकबक 18. नारी, स्त्री, महिला 21. विक्रय करना 22. वाणी, कथन, वादा 24. ताश में दस अंकों वाला पत्ता 25. नगर का, नागरिक, चतुर।

ऊपर से नीचे

1. बेफ्रिक, निश्चिंत, जिसे कोई परवाह न हो 2. मूर्ति 3. दोस्त, प्रेमी 4. कुशल, विशेषज्ञ 5. बगुला 8. झुका हुआ, झुकाया गया, नत 9. इधर-उधर, पास पड़ोस 11. किस्मत, तकदीर, भाग्य 14. बंदर, मर्कट, कपि 16. शक्तिशाली, बलवान 18. संतान, संतति 19. अस्तबल, घुड़साल 20. राजी करना, रूठे हुए को प्रसन्न करना 23. सरिता, नदिया, नद।

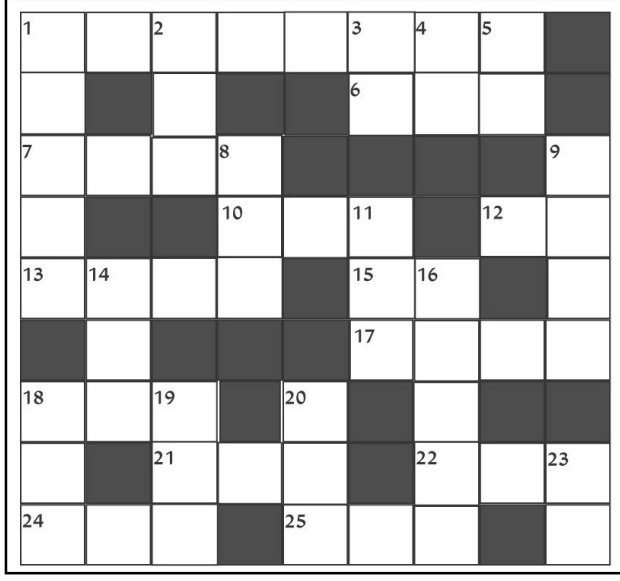

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 10 का हल

मा	म	ला	■	सि	वा	य	■	कि
लि	■	चा	ह	त	■	म	म	ता
क	सू	र	■	म	ग	न	■	ब
■	र	■	■	■	द	■	■	■
क	मा	न	■	पा	र	स	■	स
मी	■	म	जा	ल	■	न	क	ली
ना	दा	न	■	ना	र	द	■	का
■	मि	■	■	■	तौं	■	■	■
सु	नी	ल	■	अ	धी	र	■	जी

बोरियत को हमेशा न समझें नकारात्मक, कभी-कभी यह भी हो सकती है फायदेमंद

बोरियत को अक्सर एक नकारात्मक भावना के रूप में देखा जाता है। हम सोचते हैं कि बोरियत का मतलब है कि हम कुछ जरूरी नहीं कर रहे या हमारा समय बर्बाद हो रहा है। हालांकि, क्या आपने कभी सोचा है कि बोरियत भी एक तरह से हमें कुछ सिखा सकती है? इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे बोरियत हमें खुद को जानने, आराम करने और नए अनुभवों का आनंद लेने का मौका देती है।

बोरियत खुद को जानने का देती है मौका : बोरियत हमें खुद को जानने का मौका देती है। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते और बस बैठकर सोचते हैं तो हमें अपने अंदर की आवाज सुनाई देती है। यह समय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम क्या चाहते हैं और क्या हमारे लिए सच में जरूरी है। इससे हम अपनी प्राथमिकताओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपनी जिंदगी को ज्यादा अर्थपूर्ण बना सकते हैं।

बोरियत होता है आराम करने का समय : बोरियत को अक्सर समय की बर्बादी माना जाता है, लेकिन यह वास्तव में आराम करने का एक जरूरी समय होता है। जब हम लगातार काम करते रहते हैं तो हमारी ऊर्जा कम हो जाती है और हम थक जाते हैं।

बोरियत नए अनुभवों का आनंद लेने का देती है मौका : बोरियत हमें नए अनुभवों का आनंद लेने का मौका देती है। जब हम कुछ नया करने का सोचते हैं तो कई बार हमें डर लगता है या संकोच होता है। बोरियत के दौरान हम बिना किसी दबाव के नए शौक आजमा सकते हैं या नई किताबें पढ़ सकते हैं। इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है और हमारी सोच में विविधता आती है। नए अनुभवों से हमारा जीवन ज्यादा रोचक और आनंदमय बनता है।

बोरियत रचनात्मकता को देती है बढ़ावा : बोरियत रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। जब हम बोर होते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि हम नए विचारों पर ध्यान दे पाते हैं। कई बार हम ऐसी चीजें सोचते हैं, जो पहले कभी नहीं सोची थीं। इससे हमारी रचनात्मकता बढ़ती है और हम नए-नए तरीकों से समस्याओं का समाधान ढूंढ पाते हैं। बोरियत हमें अलग नजरिए से देखने की क्षमता देती है, जिससे हमारा सोचने का तरीका नया और बेहतर हो जाता है।

बोरियत मानसिक स्वास्थ्य के लिए होती है फायदेमंद : बोरियत मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। लगातार काम करते रहने से तनाव बढ़ता है, जबकि बोरियत के दौरान हमारा मन शांत रहता है। इससे हमारी मानसिक स्थिति बेहतर होती है और हम ज्यादा खुश महसूस करते हैं। इस प्रकार बोरियत केवल एक नकारात्मक भावना नहीं, बल्कि हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। यह हमें खुद को जानने, आराम करने, नए अनुभवों का आनंद लेने और रचनात्मक बनने का मौका देती है।

लोग बिना सोचे-समझे क्यों कर लेते हैं खरीदारी? जानिए इसके पीछे के कुछ कारण

बिना सोचे-समझे सामान खरीदना एक आम समस्या है, जिससे कई लोग जूझ रहे हैं। यह आदत न केवल हमारे बजट को प्रभावित करती है, बल्कि हमें आर्थिक तनाव भी दे सकती है। इस लेख में हम जानेंगे कि ऐसी खरीदारी क्यों होती है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। हम अलग-अलग मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जो इस व्यवहार को समझने में मदद करेंगे और इससे निपटने के तरीके भी जानेंगे।

भावनाओं का प्रभाव : बिना सोचे-समझे खरीदारी अक्सर हमारी भावनाओं से जुड़ी होती है। जब हम उदास, तनाव में या बोर हो रहे होते हैं तो हमें कुछ नया खरीदने का मन करता है। यह एक तुरंत मिलने वाली खुशी दे सकता है, लेकिन बाद में पछतावा हो सकता है। इस आदत को नियंत्रित करने के लिए अपनी भावनाओं को पहचानें और समझें कि कब आप ऐसी खरीदारी करने जा रहे हैं। इसके बाद खुद से पूछें कि क्या यह खरीदारी वाकई जरूरी है।

विज्ञापनों का जाल : विज्ञापन हमारे मन पर गहरा असर डालते हैं। टीवी, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने वाले विज्ञापनों में अक्सर ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं, जो हमारी जरूरत से ज्यादा होती हैं। इन विज्ञापनों को देखकर हमें लगता है कि हमें भी वही चीजें चाहिए। इससे बचने के लिए विज्ञापनों से दूरी बनाएं और केवल वही चीजें खरीदें, जो आपकी जरूरत हों। इसके अलावा विज्ञापनों पर ध्यान न दें और अपने बजट के अनुसार ही खरीदारी करें।

सुविधाजनक खरीदारी का लालच : आजकल ऑनलाइन खरीदारी बहुत आसान हो गई है। घर बैठे-बैठे आप कई चीजें मंगवा सकते हैं और वह भी बिना किसी मेहनत के। इस सुविधा का लालच हमें अक्सर बिना सोचे-समझे चीजें खरीदने पर मजबूर कर देता है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने लिए एक बजट तय करें और उसी अनुसार खरीदारी करें। इसके अलावा ऑनलाइन खरीदारी ऐप की सूचनाओं को अनसुना करें और केवल वही चीजें खरीदें, जो आपकी जरूरत हों।

छूट का मोह : छूट अक्सर हमें यह एहसास दिलाती है कि हम पैसे बचा रहे हैं, जबकि असल में हम ज्यादा खर्च कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई ऐसी चीज मिली, जिसपर 50 प्रतिशत छूट थी और आपने उसे खरीद लिया तो हो सकता है कि वह चीज आपकी जरूरत की न हो। हालांकि, आपने उसे सिर्फ छूट देखकर खरीद लिया। इससे आपका बजट बिगड़ सकता है और आपको बाद में पछतावा हो सकता है।

योजना बनाकर खरीदारी करें : बिना सोचे-समझे खरीदारी से बचने के लिए सबसे जरूरी कदम है योजना बनाकर खरीदारी करना। बाजार जाने या ऑनलाइन खरीदारी करने से पहले एक सूची बनाएं, जिसमें उन सभी चीजों का जिक्र हो, जिनकी आपको सचमुच जरूरत है। इस तरह आप अनावश्यक खर्चों से बच सकते हैं और अपने बजट को संतुलित रख सकते हैं। इसके अलावा सूचीबद्ध चीजों के अनुसार ही खरीदारी करें, ताकि आप बिना सोचे-समझे सामान खरीदने से बच सकें।

मालविका मोहनन का बोल्ड लुक देख फैंस हुए लट्टू, एक्ट्रेस ने बिकिनी में ढाया कहर

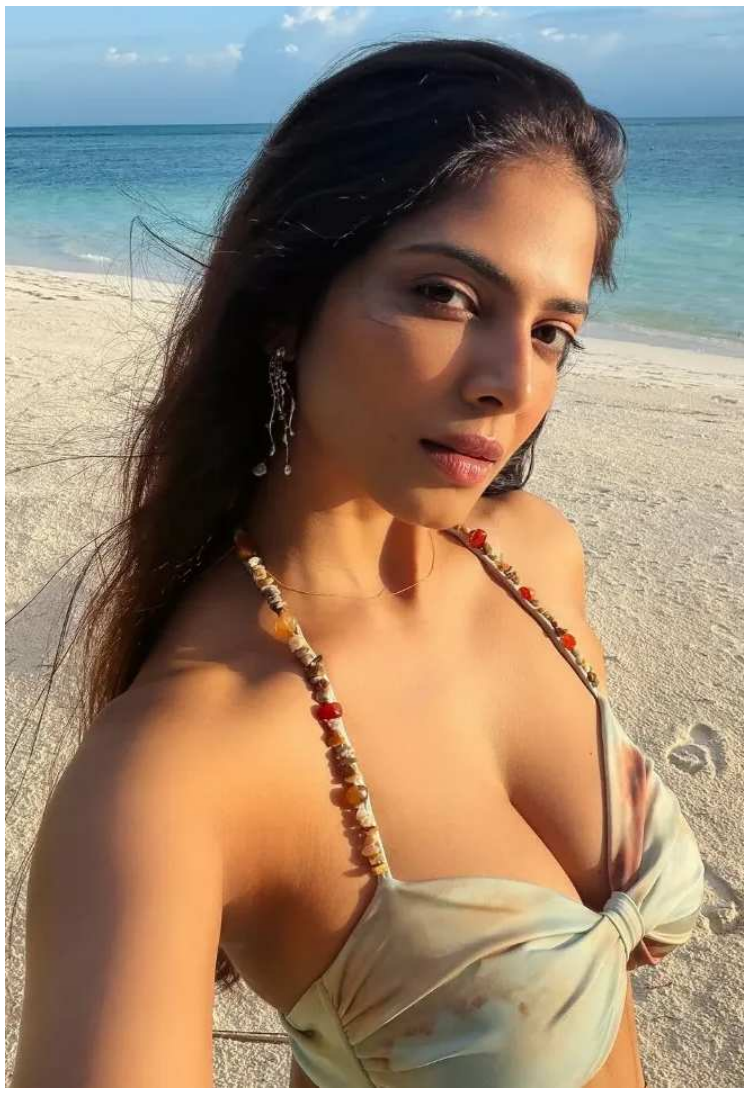

अभिनेत्री मालविका मोहनन आजकल सोशल मीडिया पर छाई हुई है. उनके सोशल मीडिया पर छाने की वजह से उनकी खूबसूरत फोटोज. जो आजकल इंटरनेट पर वायरल हो रही है. आपको बता दें कि मालविका मोहनन फैन्स की फेवरेट हीरोइन में से एक हैं. मालविका इंटरनेट पर भी काफी सक्रिय रहती हैं और फैन्स को सरप्राइज करने का मौका नहीं छोड़ती हैं. अब अभिनेत्री ने बिकिनी फोटोज से सोशल मीडिया पर पर हंगामा मचा दिया है. अभिनेत्री मालविका ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर अपनी बिकिनी फोटोज साझा की हैं, जिसमें उनका बोल्ड लुक दिखा. पेस्टल कलर की बिकिनी में मालविका किलर लगीं. बिकिनी को उन्होंने प्रिंटेड स्कार्फ से कवर किया हुआ था, जो ट्रॉपिकल लुक के लिए एकदम परफेक्ट है. नीले आसमान, रेत और पेड़ों के बीच मलाविका का हॉलिडे आउटफिट कम्फर्ट, एलीगेंस और मॉडर्न बीचवियर को दर्शाता है.जब बात हॉलिडे ड्रेसिंग की आती है, मलाविका मोहनन को पता है कि बिना किसी दिखावे के स्टाइल कैसे बनाए रखना है. उनका लेटेस्ट बीच लुक फ्रेश, मिनिमल और लग्जरी आइलैंड गेटअवे के लिए एकदम सूट करता है. अभिनेत्री मलाविका मोहनन रेत पर पेस्टल टोन की सॉफ्ट बिकिनी में क्लासी लुक से ध्यान खींचती दिखीं. स्टाइलिंग को मिनिमल रखते हुए मलाविका ने अपने आउटफिट के साथ मेटालिक बैंगल्स का स्टैक पहना.

लंबे स्टेटमेंट इयररिंग, ओपन हेयर और लाइट मेकअप से उन्होंने अपना लुक कंप्लीट किया. उनका दमकता हुआ चेहरा धूप में और भी निखरा दिखा.फैन्स मालविका के बिकिनी लुक को परफेक्ट और क्लासी बता रहे हैं. फैन्स फायर इमोजी बनकर उनके बिकिनी लुक को एक नंबर बता रहेहैं. आपको बता दें कि मालविका मोहनन ने कई मूवीज में अभिनय कर चुकी हैं.

दादा से राजकुमार राव की पहली झलक जारी

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और कप्तान सौरव गांगुली की बायोपिक को लेकर लंबे समय से चर्चा थी. सौरव गांगुली के 54वें बर्थडे पर उनकी बायोपिक दादा- द सौरव गांगुली स्टोरी का ऑफिशियली एलान हो गया है. साथ ही फिल्म में राजकुमार राव पूर्व कप्तान का रोल करने जा रहे हैं. बायोपिक दादा से राजकुमार राव का फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका है. बता दें, फिल्म के लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा. क्योंकि फिल्म इस साल नहीं बल्कि अगले साल 2027 में रिलीज होने जा रही है.

बात करें बायोपिक दादा से आए राजकुमार राव के बतौर सौरव गांगुली लुक की तो बता वह बेहद ही शानदार है. राजकुमार राव बतौर सौरव गांगुली फर्स्ट लुक में लॉर्ड्स के उस पवेलियन में टी-शर्ट उतारकर लहराते दिख रहे हैं, जैसे गांगुली ने 13 जुलाई 2002 को नेट-वेस्ट ट्राई सीरीज के फाइनल में इंग्लैंड को हराने के बाद उतारी थी. गांगुली के इस विनिंग गेस्चर पर बहुत बवाल भी हुआ था. टीम इंडिया की इंग्लैंड पर इस ऐतिहासिक जीत की आज भी चर्चा होती है. बता दें, फिल्म 14 मई 2027 को रिलीज होगी और इसे ईद के मौके पर लंबा हॉलीडे वीकेंड मिलने वाला है.

पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने अपनी बायोपिक का फर्स्ट लुक शेयर कर अपना रिएक्शन दिया है. दादा ने पोस्टर शेयर करते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, अब तक का बेस्ट गिफ्ट, मुझे अब अपना कवर ड्राइव शॉर्ट देखने का इंतजार नहीं हो रहा है.

दादा- द सौरव गांगुली स्टोरी का निर्देशन विक्रमादित्य मोटवाने ने किया है, इसे लव रंजन और अंकुर गर्ग ने प्रोड्यूस किया है. गुलशन कुमार, भूषण कुमार, टी-सीरीज़ और डीबीएल ने इसे पेश करने जा रहे हैं. यह फिल्म लव फिल्म्स के बैनर तले बनी है. गौरतलब है कि साल 2021 में सौरव ने अपनी बायोपिक का एलान किया था. बायोपिक में सौरव की शुरुआती जिंदगी से उनके बीसीसीआई अध्यक्ष बनने तक की कहानी नजर आएगी. बायोपिक का बजट बड़ा बताया जा रहा है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दादा उर्फ सौरव गांगुली की बायोपिक के लिए रणबीर कपूर और आयुष्मान खुराना का नाम भी सामने आया था. वहीं, रणबीर के मना करने के बाद आयुष्मान खुराना को रोल ऑफर हुआ था और उन्होंने फिल्म साइन भी कर ली थी, लेकिन एक्टर इस फिल्म से बाहर हो गए. वहीं, बाद में खुद सौरव गांगुली ने राजकुमार राव के नाम पर मुहर लगाई थी.

एसआईआरः आपत्तियों की सुनवाई का जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया निरीक्षण

हमारे संवाददाता

बागेश्वर। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्वाचक नामावली में पाई गई विसंगतियों से संबंधित दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया के तहत जनपद में 3 अगस्त से 31 अगस्त तक नोटिसों पर सुनवाई की जा रही है। जिसके चलते आज जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अपूर्वा पाण्डे ने बूथ संख्या-141 प्राथमिक विद्यालय बिलोना नवीन तथा बूथ संख्या-128 प्राथमिक विद्यालय खोली में चल रही नोटिस सुनवाई प्रक्रिया का निरीक्षण किया।

इस दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से सुनवाई की प्रक्रिया, अभिलेखों के रखरखाव, नोटिसों के निस्तारण की प्रगति की जानकारी ली तथा नोटिस प्राप्त मतदाताओं से भी फीडबैक प्राप्त किया। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक दावा एवं आपत्ति का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि संपूर्ण प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित हो तथा प्रत्येक पात्र मतदाता को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाए। उन्होंने बीएलओ की रिपोर्ट पर संबंधित बीएलए के हस्ताक्षर सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए।

प्राथमिक विद्यालय बिलोना नवीन मतदान केंद्र पर कुल 1008 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से 194 मतदाताओं को नोटिस प्राप्त हुए हैं। वहीं प्राथमिक विद्यालय खोली मतदान केंद्र पर कुल 675 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 133 मतदाताओं को नोटिस प्राप्त हुए हैं। इस दौरान एसडीएम प्रियंका रानी,एआरओ हेम चंद्र तिवारी, रितु गोस्वामी, सहायक निर्वाचन अधिकारी धनीराम टमटा, सुपरवाइजर परविंदर नेगी, बीएलओ शोभा देवी और नीमा देवी उपस्थित रहे।

सू- दोकू क्र.011

		3					7	
9				6		3		8
	7		9		5		6	
						1		9
3		8		7			5	
	1		3		9			7
		2		8		7		
	8				2		4	3
			1					

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.10 का हल

5	2	4	9	6	7	8	1	3
3	6	7	4	1	8	2	9	5
8	1	9	3	2	5	4	6	7
6	3	5	1	9	4	7	2	8
7	9	8	5	3	2	6	4	1
2	4	1	7	8	6	5	3	9
4	5	3	6	7	9	1	8	2
9	8	6	2	5	1	3	7	4
1	7	2	8	4	3	9	5	6

दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण कार्यों का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण

हमारे संवाददाता

चमोली। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के अंतर्गत बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड दशोली स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सगर में संचालित निर्वाचक नामावली से संबंधित दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सुनवाई प्रक्रिया का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक प्रकरण का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने प्राप्त दावों एवं आपत्तियों की स्थिति, उनके निस्तारण की प्रगति तथा अभिलेखों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र मतदाता को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए तथा पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी

चाहिए। जिलाधिकारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के द्वितीय चरण के अंतर्गत जिन मतदाताओं के नाम अभी तक मैप नहीं हो पाए हैं अथवा जिनके विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि या विसंगति है, उनके निराकरण के लिए जनपद में कैंप मोड में सुनवाई की जा रही है। इन शिविरों में बीएलओ, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) तथा संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर उपस्थित रहकर मतदाताओं से आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर रहे हैं और उनके विवरण का सत्यापन एवं मैपिंग कर रहे हैं। यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा विसंगति पाई जाती है तो उसका तत्काल निराकरण किया जा रहा है, ताकि निर्वाचन के समय किसी भी पात्र मतदाता को असुविधा का सामना न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी राजकुमार पांडे, अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।

खोया-पाया केंद्र की तत्परता से बिछड़ी 3 वर्षीय बच्ची सकुशल मिली

संवाददाता

टिहरी। पुलिस ने खोया पाया केन्द्र जानकी सेतु की तत्परता से परिवार से बिछडी तीन वर्षीय बच्ची को सकुशल बरामद कर परिवार को सौंपा।

आज यहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल श्रीमती श्वेता चौबे के निर्देशन में संचालित कांवड़ मेला-2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सहायता एवं सुविधा के लिए स्थापित खोया-पाया केंद्र निरंतर मानवीय संवेदनशीलता और तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं।

इसी क्रम में कांवड़ मेले के दौरान लगभग 03 वर्षीय एक मासूम बच्ची अपने परिजनों से बिछड़ गई। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने बच्ची को सुरक्षित संरक्षण में लेकर उसकी पहचान का प्रयास किया। बच्ची द्वारा अपना नाम एवं पता स्पष्ट रूप से न बता पाने के बावजूद पुलिस टीम ने धैर्य, संवेदनशीलता एवं सतर्कता का परिचय देते हुए सार्वजनिक उद्घोषणा, खोया-पाया तंत्र एवं अन्य माध्यमों से उसके परिजनों की तलाश शुरू की। पुलिस के त्वरित एवं अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप बच्ची के पिता एवं माता निवासी भिवानी, हरियाणा, का पता लगाया गया। आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत बच्ची को खोया-पाया केंद्र, जानकी सेतु पर सकुशल उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया गया। अपनी मासूम बच्ची को सुरक्षित वापस पाकर माता-पिता एवं अन्य परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने टिहरी पुलिस की त्वरित कार्रवाई, मानवीय संवेदनशीलता एवं सेवा-भाव की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए पुलिस टीम का हृदय से आभार व्यक्त किया। टिहरी पुलिस सभी श्रद्धालुओं से अपील करती है कि कांवड़ मेले के दौरान अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। यदि कोई बच्चा अथवा व्यक्ति अपने परिजनों से बिछड़ जाए तो घबराएं नहीं, बल्कि तत्काल निकटतम पुलिस सहायता केंद्र अथवा खोया-पाया केंद्र से संपर्क करें। टिहरी पुलिस आपकी सुरक्षा, सहायता एवं सेवा के लिए हर समय प्रतिबद्ध है।

विशेष गहन पुनरीक्षण 2026: निर्वाचक नामावली संबंधी बैठक आयोजित

हमारे संवाददाता

पौड़ी। उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई, 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत आज जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जनपद स्तरीय पदाधिकारियों, प्रतिनिधियों एवं बीएलए-1 के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी एफ. आर. चौहान ने की।

बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित पुनरीक्षण कार्यक्रम, 14 जुलाई, 2026 को प्रकाशित आलेख्य निर्वाचक नामावली, दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया तथा प्रपत्र-6, 7 एवं 8 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचक नामावली ईआरओ एवं एईआरओ कार्यालयों, बीएलओ, जिला निर्वाचन कार्यालय तथा जनपद की वेबसाइट पर अवलोकन के लिए उपलब्ध है।

अपर जिलाधिकारी एफ.आर. चौहान ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदाता सूची का गंभीरतापूर्वक परीक्षण

करने का आह्वान करते हुए कहा कि पात्र मतदाताओं के नाम हटवाने के बजाय केवल वास्तविक त्रुटियों के सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने बताया कि विसंगति (एनॉमली) एवं मानचित्रण रहित (नो मैपिंग) श्रेणी के मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से नोटिस वितरित किए जा रहे हैं। ऐसे मतदाताओं को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वे निधारित वैध अभिलेख बीएलओ को उपलब्ध कराकर अपनी मतदाता प्रविष्टि का सत्यापन तथा आवश्यक संशोधन करा सकते हैं।

बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि जनपद में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ही बीएलए-2 की नियुक्ति की गई है। अन्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से भी शीघ्र बीएलए-2 नियुक्त कर उसकी सूची जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

बैठक में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी शांतिलाल शाह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मास्टर आदर्श, उप शिक्षा अधिकारी राजेन्द्र सिंह रावत, नगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी भरत सिंह रावत, श्रीनगर विधानसभा के बीएलए प्रतिनिधि महादेव प्रसाद बहुगुणा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।

बनबसा रेलवे स्टेशन पर अछनेरा-टनकपुर एक्सप्रेस का ठहराव हुआ स्वीकृत

हमारे संवाददाता

चम्पावत। जनपद एवं सीमांत क्षेत्र के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात के रूप में बनबसा रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 15093/15094 अछनेरा–टनकपुर एक्सप्रेस के ठहराव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। भारत सरकार के रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्कर सिंह धामी को भेजे पत्र में अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री द्वारा 8 जुलाई 2026 को जनसुविधा के दृष्टिगत बनबसा रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी के ठहराव का अनुरोध किया गया था। इस अनुरोध पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए बनबसा रेलवे स्टेशन पर अछनेरा–टनकपुर एक्सप्रेस के ठहराव की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से जनपद चम्पावत एवं आसपास के क्षेत्रों के लोगों को एक महत्वपूर्ण रेल सुविधा प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से यात्रियों को आवागमन में अधिक सुविधा मिलेगी तथा पर्यटन, व्यापार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। जिलाधिकारी ने इस जनहितकारी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री एवं रेल मंत्रालय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सुविधा सीमांत क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगी और क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

महाराष्ट्र कांग्रेस द्वारा सुनित्रा पवार पर की गई अभद्र टिप्पणी निंदनीयः सौरभ

हमारे संवाददाता

नई दिल्ली/देहरादून। एनसीपी युवा (एनडीए) के राष्ट्रीय सचिव सौरभ आहूजा ने महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं द्वारा महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री सुनित्रा पवार पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। सौरभ आहूजा ने मीडिया को जारी अपने बयान में कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली भाषा या व्यक्तिगत टिप्पणियां स्वीकार्य नहीं हो सकतीं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस को अपनी मर्यादा में रहकर राजनीति करनी चाहिए तथा किसी भी महिला के प्रति टिप्पणी करते समय संयम और सम्मान का परिचय देना चाहिए।

उन्होने कहा कि महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले राजनीतिक दलों को अपने नेताओं की भाषा और आचरण पर भी समान रूप से ध्यान देना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि महाराष्ट्र कांग्रेस इस मामले में जिम्मेदारी का परिचय देगी और भविष्य में इस प्रकार की टिप्पणियों से बचेगी। उन्होंने कहा उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।

रुद्रपुर महाविद्यालय में बीपी स्क्रीनिग जागरूकता विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

रुद्रपुर (सं)। सरदार भगतसिंह राजकीय स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर में हेल्थ एंड हैप्पीनेस क्लब की ओर से take charge at 18 & National B.P. स्क्रीनिंग जागरूकता पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की संयोजक प्रो. दीपा वर्मा के स्वागत उद्बोधन के पश्चात कार्यक्रम में पधारे मुख्य वक्ता डॉ. एसपी सिंह ने अपना उद्बोधन दिया। डॉ सिंह, डॉ. रहमान, वीर सिंह मौर्या एवं उनकी टीम ने ब्लड प्रेशर से सम्बंधित छात्र छात्राओं को विस्तृत जानकारी दी। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एएन सिंह ने विद्यार्थियों को बताया कि बी पी जैसी गम्भीर बीमारी में प्रारंभिक निदान से ही भविष्य में होने वाली गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता हैं। कार्यक्रम का संचालन प्रो दीपा वर्मा ने किया। इस कार्यशाला में डॉ.अमिता,डॉ. भरत सिंह डॉ. प्रेम प्रकाश डॉ चारु चन्द्र,डॉ. वसुंधरा, डॉ. पूनम रौतेला, डॉ. कमला बोरा, डॉ. खान डॉ दीपचंद्र, डॉ. रिछारिया डॉ. नीलोफर, डॉ स्निग्धा,डॉ अपर्णा डॉ. सुमन, डॉ.पूजा, डॉ. बी पी. सिन्हा, डॉ. मनीषा, डॉ. डॉ रोहित एवं महाविद्यालय के अनेक छात्र छात्राएं उपस्थित थे।

'बंद कमरे' और पहाड़ के 'खाली गाँव'..

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

पूछेगी कि बैठक में मेरे गाँव की बात हुई थी क्या? मेरे बेटे की नौकरी पर चर्चा हुई थी क्या? मेरे स्कूल, मेरे अस्पताल और मेरी सड़क का भी कोई एजेंडा था क्या? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो बैठक सफल मानी जाएगी और अगर जवाब केवल चुनावी समीकरणों तक सीमित रहा, तो यह बैठक भी राजनीतिक कैलेंडर की एक और तारीख बनकर रह जाएगी। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी बैठक अंततः दिल्ली के बंद कमरों में नहीं, बल्कि जनता के खुले दरबार में होती है।

मुख्य सचिव ने दिये अंडरग्राउंड विद्युत लाइन परियोजनता का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश

संवाददाता

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने ऊर्जा विभाग के अंतर्गत मसूरी एवं नैनीताल के लिए अंडरग्राउंड विद्युत लाइन परियोजना का प्रस्ताव तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं।

आज यहां मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने वाह्य सहायतित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने इसके तहत् पूर्ण हो चुकी, गतिमान एवं भावी परियोजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी ली एवं दिशा निर्देश दिए। उन्होंने वाह्य सहायतित परियोजनाओं के अंतर्गत प्रदेश में आधारभूत संरचनाओं के विकास पर फोकस किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की क्लोजर रिपोर्ट फंडिंग एजेंसी, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार एवं भारत सरकार में अपने लाइन डिपार्टमेंट को अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि धीमी गति से चल रहे सभी प्रोजेक्ट्स की लगातार निगरानी करते हुए आवश्यक

कदम उठाए जाएँ।

उन्होंने प्रोजेक्ट्स को समय से पूर्ण किए जाने हेतु मैनपावर और मशीन बढ़ाते हुए सभी आवश्यक कदम उठाये जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग के अंतर्गत मसूरी एवं नैनीताल के लिए अंडरग्राउंड विद्युत लाइन परियोजना का प्रस्ताव तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट में तेजी लाए जाने के लिए डेडिकेटेड पीएमयू स्थापित किए जाने की बात कही। कहा कि डेडिकेटेड पीएमओ और लगातार निगरानी करते हुए प्रोजेक्ट को समय से पूर्ण किया जाए। मुख्य सचिव ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर तकनीकी शिक्षा में सिस्टम को मजबूत किए जाने की दिशा में कार्य किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा के में इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक और आईटीआई में आधारभूत संरचना विकास पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा इसके लिए ईएपी वित्तपोषित प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाएं, साथ ही रिवर रेज्युविनेशन, पशुपालन, डेरी और फिशरीज के उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया जाए। इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव नितेश कुमार झा, दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, रणजीत सिंह चौहान, विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव विनीत कुमार एवं हिमांशु खुराना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

ढोल बजाकर खोली अपराधी की पोल

संवाददाता

देहरादून। हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे आरोपी के घर के बाहर पुलिस ने ढोल बजाकर मुनादी करायी।

मिली जानकारी के अनुसार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त आरोपियों के साथ-साथ विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे लोगों की गिरफ्तारी हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के एसएसपी देहरादून सभी अधीनस्थों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशों के अनुपालन में दून पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कोतवाली नगर में पंजीकृत मुकदमें में वांछित आसिफ बाबा उर्फ आसिफ मलिक जिसके द्वारा व अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 28 जून 2026 को एमजे टॉवर के बेसमेंट में एक व्यक्ति प्रियांश जैन के साथ मारपीट कर उस पर धारधार हथियारो से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें लगातार प्रयासरत थी पर आसिफ अपनी गिरफ्तारी से बचते हुए लगातार फरार चल रहा था, जिसके विरुद्ध पूर्व में न्यायालय से गैर जमानती वारंट प्राप्त कर गिरफ्तारी के प्रयास किए गए परंतु उसके लगातार फरार रहने पर पुलिस द्वारा आसिफ मलिक पुत्र मोहम्मद यासीन, निवासी मेहुवाला, नया नगर, थाना पटेलनगर, जनपद देहरादून के विरुद्ध 84 बीएनएसएस की कार्यवाही हेतु न्यायालय से आदेश प्राप्त करते हुऐ आज उद्घोषणा की प्रक्रिया में उसके निवास स्थान तथा सार्वजनिक स्थान/मुख्य चौराहे पर ढोल-नगाड़ो के साथ दो गवाहों के समक्ष कराई गई तथा उसके मकान के मुख्य गेट सहित मोहल्ले के मुख्य-मुख्य स्थानों व चौराहों पर धारा 82 सीआरपीसी की उद्घोषणा चस्पा की गई। मुनादी के दौरान आसिफ को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने तथा ऐसा न करने पर न्यायालय के आदेशानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करने संबंधी उद्घोषणा की गई।

धराली आपदा का एक वर्ष पूराः खोखले दावों के मलबे में दबी जनता

पुनर्वास और मुआवजे के मोर्चे पर उत्तराखण्ड सरकार नाकामः कांग्रेस

हमारे संवाददाता

देहरादून। उत्तरकाशी के धराली (भागीरथी घाटी) में आई भीषण जल-प्रलय को आज पूरा एक वर्ष बीत चुका है। पिछले साल 5 अगस्त 2025 को आई इस तबाही ने दर्जनों मासूम जिंदगियां निगल ली थीं और सैकड़ों परिवारों के आशियाने, होटल तथा आजीविका के मुख्य साधन (सेब के बाग) मलबे के ढेर में तब्दील कर दिए थे। आपदा की पहली बरसी पर आज प्रदेश प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह ने सरकार की घोर संवेदनहीनता, लचर पुनर्वास नीति और नाकामी पर तीखा हमला बोला है।

डॉ. प्रतिमा सिंह ने जारी बयान में सरकार के उन दावों की हवा निकाल दी है जिसमें विकास के बड़े-बड़े आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत यह है कि एक साल बाद भी प्रभावित जनता दाने-दाने को मोहताज है और सरकार केवल कागजी घोड़ों और चंद रुपयों के ऊंट के मुंह में जीरा समान मुआवजे के सहारे अपनी नाकामी छुपाने का प्रयास कर रही है, उन्होंने कहा कि करोड़ों के नुकसान पर चंद रुपयों का भद्दा मजाक करने का कार्य सरकार ने किया है धराली बाजार के जिन स्थानीय व्यवसायियों के करोड़ों रुपये के होटल, गेस्ट हाउस और होमस्टे मलबे में विलीन हो गए, उन्हें सरकार ने आपदा राहत मैनुअल के नाम पर महज चंद रुपये थमा दिए। यह राशि एक कमरा बनाने के लिए भी नाकाफी है। व्यापारियों का व्यापार ठप है और वे कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं। उजड़े सेब के बागान और आजीविका पर चौतरफा मार हुई उसके बाद भी सरकार इतनी असंवेदनशील है,धराली और हर्षिल घाटी की आजीविका की रीढ़ कहे जाने वाले सेब के सैकड़ों बगीचे आज भी मलबे के नीचे दबे हैं। सरकार भूमि के पुनरुद्धार और किसानों को दीर्घकालिक आर्थिक पैकेज देने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होने कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग की बदहाली और असुरक्षित बुनियादी ढांचा आज भी आम जन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं सरकार गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू रखने की पीठ थपथपा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि बीआरओ द्वारा बनाए गए अस्थायी मार्ग बेहद जानलेवा हैं। हालिया मानसून में भटवाड़ी और धराली के पास हाईवे पर आई 70 मीटर लंबी गहरी दरारें और भू-धंसाव यह साबित करते हैं कि सरकार ने पिछले एक साल में केवल लीपापोती की है, कोई ठोस और वैज्ञानिक निर्माण नहीं किया।

प्रदेश प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह ने सरकार को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि आपदा प्रभावितों की इस अनदेखी के खिलाफ अब प्रदेश की जनता चुप नहीं बैठेगी।

‘पोस्टर क्रांति’ की सियासी दुकानों पर ताला

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में एक खबर आई है। खबर छोटी लग सकती है, लेकिन उसके भीतर लोकतंत्र का एक बड़ा सवाल छिपा हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड के 17 पंजीकृत राजनीतिक दलों को अपनी सक्रिय सूची से हटा दिया है। अब यह दल आगामी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, जब तक वह निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी कर दोबारा मान्यता या पंजीकरण हासिल न कर लें। पहली नजर में लगेगा कि इससे क्या फर्क पड़ता है? चुनाव तो भाजपा और कांग्रेस ही लड़ती हैं। लेकिन जरा ठहरिए। सवाल केवल 17 दलों का नहीं है, सवाल यह है कि हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक दल बनाना कितना आसान और उसे जीवित रखना कितना कठिन है। उत्तराखंड में पिछले दो दशकों में दर्जनों राजनीतिक दल बने। किसी ने पर्वतीय अस्मिता के नाम पर पार्टी बनाई, किसी ने पलायन के मुद्दे पर, किसी ने रोजगार के लिए और किसी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ। चुनाव आए, पोस्टर लगे, प्रेस कान्फ्रेंस हुई, सोशल मीडिया पर क्रांति भी हुई। लेकिन चुनाव खत्म होते ही अधिकांश दल भी मानो राजनीतिक स्मृति से गायब हो गए।

निर्वाचन आयोग का यह कदम बताता है कि केवल पार्टी का नाम रख लेने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सक्रिय संगठन, नियमित राजनीतिक गतिविधियां, कानूनी अनुपालन और जनता के बीच निरंतर उपस्थिति भी जरूरी होती है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। क्या यह केवल 17 दलों की विफलता है? या फिर यह उस राजनीतिक व्यवस्था की भी विफलता है जिसमें छोटे दलों के लिए जगह लगातार सिकुड़ती जा रही है? आज चुनाव लड़ना विचारों से ज्यादा संसाधनों का खेल बनता जा रहा है। बड़े दलों के पास करोड़ों का प्रचार, डिजिटल अभियान, विशाल संगठन और संसाधन हैं। दूसरी ओर, छोटे दल चुनाव आयोग के नियमों, वित्तीय रिपोर्टिंग, संगठनात्मक ढांचे और आर्थिक चुनौतियों के बीच दम तोड़ देते हैं। ऐसे में लोकतंत्र का मैदान बराबरी का नहीं रह जाता।

❑प्रदेश के 17 राजनीतिक दलों पर गिरी गाज, सक्रिय सूची से बाहर
❑जनादेश के अभाव में वक्त के साथ राजनीतिक स्मृति से हुए ओझल
❑जनमुद्दों से जन्मी सियासी उम्मीदें ने चंद चुनावों के बाद ही तोड़ा दम
❑राजनीति में कागजी पार्टियों का अंत और हो गया नए खेल की शुरु

उत्तराखंड जैसे राज्य में यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह वही प्रदेश है जिसकी नींव जनआंदोलनों पर पड़ी थी। अलग राज्य की मांग किसी एक बड़ी पार्टी ने नहीं, बल्कि छोटे संगठनों, सामाजिक आंदोलनों और हजारों आम लोगों ने मिलकर उठाई थी। अगर छोटे राजनीतिक विकल्प धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगे, तो क्या भविष्य में नए विचारों को राजनीति में जगह मिल पाएगी? हालांकि, इसका मतलब यह भी नहीं कि केवल नाम के लिए राजनीतिक दल बने रहें। यदि कोई पार्टी वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ती, अपना लेखा-जोखा जमा नहीं करती, संगठन नहीं चलाती और केवल कागजों पर मौजूद रहती है, तो निर्वाचन आयोग की कार्रवाई लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा मानी जाएगी। चुनाव आयोग का दायित्व केवल चुनाव कराना नहीं, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था को पारदर्शी और नियमबद्ध बनाए रखना भी है। अब सवाल उत्तराखंड की राजनीति का है।

2027 का विधानसभा चुनाव धीरे-धीरे करीब आ रहा है। भाजपा सत्ता बचाने की तैयारी में है। कांग्रेस वापसी का सपना देख रही है। क्षेत्रीय दल अपनी प्रासंगिकता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में 17 दलों का बाहर होना चुनावी गणित को भले बहुत बड़ा झटका न दे, लेकिन यह संकेत जरूर देता है कि आने वाले समय में चुनावी मुकाबला और अधिक सीमित हो सकता है। लोकतंत्र की खूबसूरती विकल्पों में होती है। विकल्प खत्म होने लगें, तो चुनाव तो होते हैं, लेकिन राजनीतिक विविधता कमजोर पड़ जाती है। इसलिए यह खबर केवल इतनी नहीं है कि 17 दल सूची से हट गए। असली खबर यह है कि उत्तराखंड की राजनीति में विचारों की जमीन कितनी बची है? क्या नए राजनीतिक प्रयोगों के लिए जगह है? क्या छोटे दल संगठन और जवाबदेही के साथ खुद को खड़ा कर पाएंगे? या फिर राजनीति कुछ बड़े दलों के बीच ही सिमटती चली जाएगी?

लोकतंत्र में चुनाव जीतना ही सब कुछ नहीं होता। लोकतंत्र का स्वास्थ्य इस बात से भी तय होता है कि कितनी आवाजें मैदान में हैं, कितने विचार जनता तक पहुंच रहे हैं और कितने राजनीतिक दल केवल चुनाव नहीं, समाज के सवालों को भी जिंदा रखे हुए हैं। सवाल 17 दलों के हटने का नहीं है। सवाल यह है कि उत्तराखंड की राजनीति में अगला नया विकल्प कौन बनेगा या फिर विकल्प बचेंगे भी या नहीं?

सोशल मीडिया पर फेमस होने का शौक पड़ा भारी!

संवाददाता

देहरादून। सोशल मीडिया प्लेटफार्म में फेमस होने के जनून ने युवक को थाने पहुंचाया। पुलिस ने मोटरसाईकिल सीज कर युवक को वर्निंग देकर छोड दिया। आज यहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल एक वीडियो, जिसमें मोटर साईकिल सवार व्यक्ति द्वारा पीछे कमर में पिस्टलनुमा लाइटर लगाकर राजपुर रोड पर मोटर साईकल चलाकर आमजन में भय फैलाने के वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल द्वारा तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु थानाध्यक्ष राजपुर को निर्देश दिए गए। जिस पर राजपुर पुलिस द्वारा तत्काल उक्त व्यक्ति एवं वाहन को ट्रेस कर युवक को हिरासत मे लिया गया। उक्त वाहन को चालक गौरव कुमार पुत्र सिताब सिंह निवासी हिम्मतनगर, सहारनपुर उम्र 18 वर्ष चला रहा था। जानकारी करने पर उसके द्वारा शॉपिंग ऐप के माध्यम से पिस्टल नुमा गैस लाइटर शौकिया तौर पर वीडियो बनाने के मंगवाया गया था। पुलिस द्वारा युवक को सख्त हिदायत देते हुए उक्त मोटरसाइकिल को सीज कर पिस्टलनुमा गैस लाइटर को बरामद किया गया।

सिद्धिविनायक मंदिर में दान चोरी का आरोप, सरकार ने मंदिर ट्रस्ट से मांगा हिसाब

संवाददाता

मुंबई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई के मशहूर श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में 18 करोड़ रुपये की दान चोरी का दावा किया है। अब इस मामले में महाराष्ट्र के कानून और न्याय विभाग ने सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट से डिटेल्ड फाइनेंशियल रिपोर्ट मांगी है। महाराष्ट्र के कानून और न्याय विभाग की तरफ से रिपोर्ट तलब किए जाने पर मंदिर ट्रस्ट ने अपना पक्ष रखा है। ट्रस्ट ने दान में हेरफेर का मामला सामने आने के बाद रिपोर्ट मांगने के दावों से इनकार किया है। मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि कानून और न्याय विभाग का ताजा कदम उसकी गुजारिश पर ही आया है। ट्रस्ट ने बताया कि इस साल मई में उसने ही विभाग से मंदिर के डिटेल्ड ऑडिट की गुजारिश की थी, जो इन आरोपों के सामने आने से कई महीने पहले की गई थी। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन और शिवसेना नेता सदानंद सरवणकर ने बताया कि चढ़ावे की चोरी के मामले में नौ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा, ‘हमने जहां भी जरूरी था, वहां मामले दर्ज कराए है।

नहीं रहे फिल्म अभिनेता प्रदीप रावत

संवाददाता

मुंबई। बॉलीवुड के फेमस एक्टर प्रदीप रावत के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। उनके निधन से इंडस्ट्री को भारी नुकसान पहुंचा है। टीवी से बॉलीवुड तक पर छाने वाले प्रदीप रावत के निधन से उनके फैंस की आंखें भी नम हो गई हैं। 74 साल की उम्र में एक्टर का निधन कैंसर से हुआ है। वहीं इस दुखद खबर की जानकारी उनके करीबी दोस्त और बॉलीवुड एक्टर यशपाल शर्मा ने उनके फैंस के साथ शेयर की है।

उनका पार्थिव शरीर आज दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक मुंबई के गोरेगांव वेस्ट स्थित इम्पीरियल हाइट्स में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद शाम 4 बजे उनके पार्थिव शरीर को जोगेश्वरी वेस्ट स्थित ओशिवारा श्मशान घाट ले जाया जाएगा, जहां पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान उनके परिवार और करीबी मौजूद होंगे। वहीं परिवार और प्रशंसक उन्हें नम आंखों से विदाई भी देंगे।

प्रदीप रावत कई फिल्मों में काम कर अपनी एक्टिंग से ऑडियंस का दिल जीत चुके थे। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत साल 1985 में आई फिल्म ‘मेरी जंग’ से की थी। हालांकि इस फिल्म में उनका किरदार छोटा था। इसके बाद उन्होंने ‘महाभारत’ में ‘अश्वत्थामा’ का किरदार निभाया। वहीं साल 2005 में आई फिल्म ‘गजनी’ में एक्टर ने विलेन का किरदार निभाया था, जिसे लोगों ने खूब पसंद भी किया था।

आसमान से निगरानी, जमीन पर तुरंत कार्रवाई

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। नगर आयुक्त, नंदन कुमार के निर्देशों के क्रम में नगर निगम हरिद्वार ने कांवड़ मेला-2025 में सफलतापूर्वक अपनाई गई ड्रोन आधारित निगरानी व्यवस्था को इस वर्ष कांवड़ मेला-2026 में और अधिक उन्नत एवं प्रभावी स्वरूप दिया है। करोड़ों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण पूरे कांवड़ मार्ग पर प्रत्येक स्थान की लगातार मानवीय निगरानी करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। ऐसे में नगर निगम ने आसमान से रियल-टाइम निगरानी को अपना सबसे प्रभावी हथियार बनाया है।

अब ड्रोन पूरे कांवड़ मार्ग पर लगातार उड़ान भरकर उन स्थानों की पहचान कर रहे हैं जहाँ सामान्य निरीक्षण दलों की नजर तुरंत नहीं पहुँच पाती। यदि कहीं भी झाड़ियों, डिवाइडरों, बैरिकेडिंग

के पीछे अथवा भीड़ के बीच छिपा हुआ कूड़ा दिखाई देता है, तो ड्रोन टीम तत्काल उस स्थान का फोटोग्राफ एवं जियोटैग लोकेशन नगर निगम के विशेष व्हाट्सएप कमांड ग्रुप पर साझा करती है। इस कमांड ग्रुप में सभी संबंधित सफाई निरीक्षक, जोन प्रभारी एवं ड्रोन टीम के सदस्य जुड़े हुए हैं। फोटो अपलोड होते ही संबंधित सफाई निरीक्षक को टैग किया जाता है और तत्काल सफाई दल मौके पर भेजा जाता है। सफाई कार्य

◆कांवड़ मेला-2026: नगर निगम का अपग्रेडेड ड्रोन कमांड सिस्टम

पूर्ण होने के बाद उसी स्थान की ‘आफ्टर क्लीनिंग’ फोटो पुनः ग्रुप में साझा की जाती है, जिससे कंट्रोल रूम यह सुनिश्चित करता है कि शिकायत का वास्तविक एवं संतोषजनक निस्तारण हो चुका है। इससे पूरी व्यवस्था रियल-टाइम, पारदर्शी एवं जवाबदेह बन गई है।

ड्रोन तकनीक का उपयोग केवल गंदगी की पहचान तक सीमित नहीं है। यदि कांवड़ मार्ग पर कहीं भी कोई पशु विचरण करता हुआ दिखाई देता है, तो ड्रोन टीम तत्काल उसकी सटीक लोकेशन साझा करती है। सूचना मिलते ही नगर निगम की संबंधित टीम मौके पर पहुँचकर आवश्यक कार्रवाई करती है, जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं निर्बाध आवागमन सुनिश्चित हो सके।

नगर आयुक्त नंदन कुमार ने कहा कि नगर निगम हरिद्वार का उद्देश्य केवल सफाई करना नहीं, बल्कि तकनीक के माध्यम से स्वच्छता प्रबंधन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाना है।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, *एडवोकेट*
बैजनाथ, *एडवोकेट*

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्री के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।